चक्रीय अर्थव्यवस्था वाले विश्व की रचना

अतुल बगई | भारत कार्यालय के देश प्रमुख, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ईमेल: bagai@un.org.

मनीषा चौधरी | कार्यक्रम अधिकारी, यूएनईपी (भारत)। ईमेल: manisha.choudhary@un.org

भारत की अध्यक्षता में जी20 द्वारा अपनाए गए सतत विकास के लिए जीवन शैली पर उच्च-स्तरीय सिद्धांत स्थायी उपभोग और उत्पादन को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धताओं की आवश्यकता को दर्शाते हैं। यह समय सभी की आधारभूत जरूरतों को पूरा करते हुए वैश्विक भौतिक पदचिह्न को घटाने के लिए सामूहिक कार्रवाई का है। ऐसा करने में विभिन्न विकासात्मक आवश्यकताओं और राष्ट्रीय परिस्थितियों की पूर्ती करते हुए चक्रीय और हरित आर्थिक विकास को अपनाने के लिए सक्षम स्थितियों का सृजन अनिवार्य है।

विश्व की जनसंख्या 2050 तक लगभग 10 अरब हो सकती है। इसका अर्थ होगा खाद्यान्न, फैशन, यात्रा, आवास और अन्य संबंधित उत्पादों और सेवाओं की अधिक मांग। जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए पदार्थों का वार्षिक वैश्विक निष्कर्षण पहले ही 22 अरब टन (1970) से बढ़कर 70 अरब टन (2010) हो गया है और 2060 तक इसके लगभग दोगुना होने की संभावना है। इस वर्ष आठ महीने से भी कम समय में ही मानवजाति की पर्यावरणीय संसाधन और सेवाओं की मांग 2023 में पृथ्वी द्वारा पुनर्जीवित की जा सकने वाली क्षमता से अधिक हो गयी है और हमारी खपत की दर लगातार बढ़ रही है। इससे पृथ्वी के सीमित प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है जिससे संसाधन असुरक्षा उत्पन्न हो रही है और जैव विविधता की क्षति, प्रदूषण, उत्सर्जन में बढ़ोतरी और जलवायु परिवर्तन हो रहा है।

जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन पर सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी 12) के अनुरूप अधिक टिकाऊ जीवन शैली और एक उचित परिवर्तन को अपनाना जलवायु और प्रकृति को बेहतर बनाने की हमारी आकांक्षा की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण होगा। हालांकि इस परिवर्तन के लिए युक्तिपूर्ण नीतियों, उत्पादों, कम-कार्बन फुटप्रिंट विकल्पों, बुनियादी ढांचे, सेवाओं,

प्रौद्योगिकियों और सभी क्षेत्रों में क्षमता निर्माण को सक्षम करने में काफी निवेश की आवश्यकता होगी।

उपभोग और उत्पादन की अधिक टिकाऊ व्यवस्थाओं की ओर बढ़ने और उत्पादों के संचलन की अविलंब आवश्यकता है। 'सर्कुलरिटी' (उत्पादों या उत्पादों के हिस्सों के पुनः उपयोग) एक संकल्पना है जिसके अनुसार उत्पादों का उपयोग उच्चतम उपयोगिता पर यथासंभव लंबे समय तक किया जाता है। सर्कुलरिटी में उत्पादों और पदार्थों के पूरे जीवनचक्र का समावेश होता है, उत्पादों को लंबे समय तक चलने वाले और मरम्मत योग्य बनाने से लेकर यह सुनिश्चित करने तक की सामग्री को रीसाइक्लिंग (पुनर्प्रयोग) के माध्यम से वापिस पाया जा सकता है और इस प्रकार किसी उत्पाद के जीवनचक्र के अंत तक उसे अर्थव्यवस्था में कायम रखा जा सकता है। सर्कुलरिटी का मुख्य उद्देश्य अव्यवहार्य उपभोग और उत्पादन के हानिकारक पर्यावरणीय और सामाजिक-आर्थिक प्रभावों को कम करना है जिसके परिणामस्वरूप उपभोग-जनित पर्यावरणीय क्षरण और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी आती है। सर्कुलरिटी के लक्ष्यों में अपशिष्ट उत्पादन को रोकना और कम करना भी शामिल है। चक्रीय अर्थव्यवस्था हरित रोजगारों और चक्रीय व्यापार के अवसर पैदा करके समाजों को बेहतर संभावनाएं प्रदान करती है।

हमारी जीवनशैली के तौर-तरीके चक्रीय आर्थिक विकास की परिवर्तन अवस्था को अर्थपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। प्रमाण साक्षी हैं कि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का दो-तिहाई भाग सीधे तौर पर घरों और जीवनशैली से जुड़ा है। स्थायी और कम-कार्बन उत्सर्जन जीवन शैली प्राप्त करने के लिए चार आवश्यक क्षेत्र हैं गतिशीलता, आवास और ऊर्जा का उपयोग, आहार विकल्प, भोजन और नए व्यवसाय मॉडल। इन क्षेत्रों में स्थिरता पर व्यक्तिगत स्तर के प्रभाव की गुंजाईश है। नए व्यवसाय मॉडल के तहत फैशन उद्योग को नए सिरे से विचार की जरूरत है। यूएनईपी की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 15 वर्षों में, फैशन के क्षेत्र में खपत दोगुनी से अधिक हो गई है जबकि किसी वस्त्र को रद्द करने से पहले उसे पहनने की संख्या में 36 प्रतिशत की कमी आई है। हर सेकंड दुनिया भर में एक कचरा ट्रक भर कपड़ों को जिनकी अनुमानित कीमत 460 अरब डॉलर है फेंक दिया जाता है। वर्तमान उपभोग प्रवृत्तियों और अनुमानों के आलोक में फैशन उद्योग अभी तक चक्रीयता की राह पर नहीं है। वर्तमान फैशन उद्योग की स्थिरता को बढ़ाने के लिए कपड़ा मूल्य श्रृंखला में कार्रवाई की आवश्यकता है।

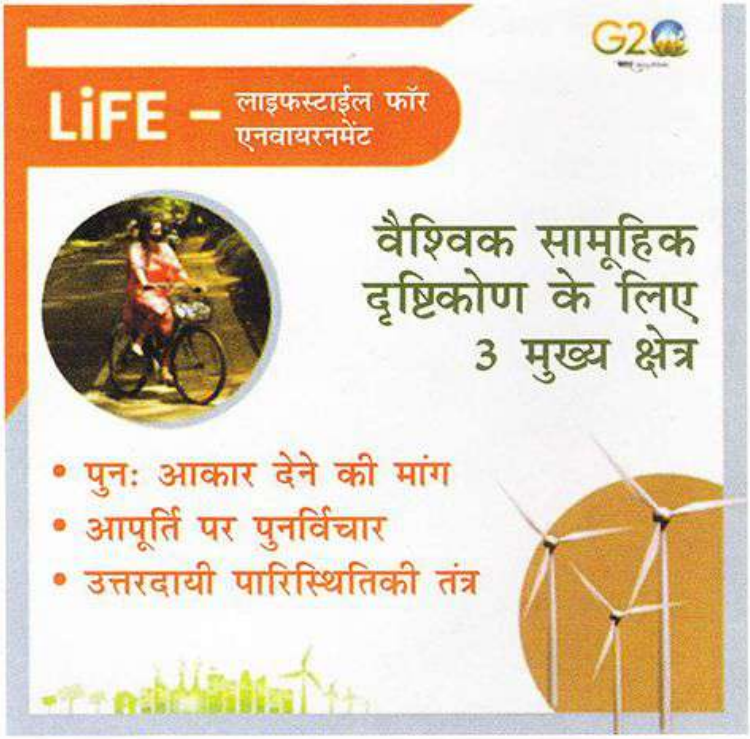

सर्कुलरिटी, सतत उपभोग और उत्पादन पर जी20 देशों का अधिक जोर

भारत की अध्यक्षता में जी20 द्वारा अपनाए गए सतत विकास के लिए जीवन शैली पर उच्च-स्तरीय सिद्धांत स्थायी उपभोग और उत्पादन को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धताओं की आवश्यकता को दर्शाते हैं। जी20 पर्यावरण और जलवायु मंत्रियों की बैठक के परिणाम दस्तावेज सहित उच्च-स्तरीय सिद्धांत सतत विकास हासिल करने में चक्रीय अर्थव्यवस्था और संसाधन दक्षता द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देते हैं। यह समय सभी की आधारभूत जरूरतों को पूरा करते हुए वैश्विक भौतिक पदचिह्न को घटाने के लिए सामूहिक कार्रवाई का है। ऐसा करने में विभिन्न विकासात्मक आवश्यकताओं और राष्ट्रीय परिस्थितियों की पूर्ती करते हुए चक्रीय और हरित आर्थिक विकास को अपनाने के लिए सक्षम स्थितियों का सृजन अनिवार्य है।

विभिन्न विकासात्मक आवश्यकताओं और राष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए चक्रीय और हरित आर्थिक विकास में परिवर्तन।

एक भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण के रूप में और जी20 देशों की प्रतिबद्धताओं को साकार रूप देने, जलवायु आपदा से निपटने और सतत विकास लक्ष्यों एवं जलवायु, जैव विविधता और प्रदूषण के अन्य वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वर्तमान खपत और उत्पादन के तौर तरीकों की सम्पूर्ण व्यवस्था में अविलंब परिवर्तन सर्वोपरि है। कई क्षेत्रों विशेष रूप से अर्थव्यवस्था के उच्च प्रभाव वाले क्षेत्रों (परिवहन, कपड़ा, प्लास्टिक, भवन और निर्माण आदि) में आमूलचूल आपूर्ति बदलाव की आवश्यकता है। पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक संकटों से उत्पन्न मानवजाति के सामने आने वाली चुनौतियों का साथ मिलकर उनकी भयावहता के अनुरूप गति और परिमाण से निपटा जाना चाहिए। साथ ही, प्रत्येक देश के विशिष्ट सरोकारों को भी समझा जाना चाहिए।

भारत के सकारात्मक पहलों में चक्रीय आर्थिक विकास में परिवर्तन की क्षमता

भारत सरकार चक्रीय अर्थव्यवस्था, संसाधन दक्षता और टिकाऊ उपभोग और उत्पादन के महत्व पर विशेष जोर दे रही है। विनिर्माण-आधारित विकास की दिशा में भारत का उन्मुख होना विनिर्माण क्षेत्रों में चक्रीय अर्थव्यवस्था प्रयासों को एकीकृत करने का एक उल्लेखनीय अवसर प्रदान करता है। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार चक्रीय आर्थिक विकास में परिवर्तन से भारत में 2050 तक सामान्य व्यवसाय परिदृश्य के सापेक्ष लगभग 624 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक मूल्य का शुद्ध आर्थिक लाभ उत्पन्न हो सकता है। चक्रीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन से वैश्विक रोजगार और हरित नौकरियां बढ़ सकती हैं: अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के अनुमान के अनुसार चक्रीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन से वैश्विक रोजगार में छह मिलियन नौकरियों की वृद्धि हो सकती है।'

संसाधनों के कुशल उपयोग और चक्रीय आर्थिक विकास की दिशा में भारत द्वारा की गई कुछ पहलों में राष्ट्रीय संसाधन दक्षता नीति (2019) मसौदा, स्टील स्क्रैप रीसाइक्लिंग नीति, वाहन स्क्रैपिंग नीति और चक्रीय अर्थव्यवस्था पर हाल ही में विकसित क्षेत्रीय कार्य योजनाएं शामिल हैं।

उपरोक्त के अलावा, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत प्लास्टिक पैकेजिंग पर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) पर हाल ही में अधिसूचित दिशानिर्देश प्लास्टिक पैकेजिंग कचरे की चक्रीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं और व्यवसायों द्वारा टिकाऊ प्लास्टिक पैकेजिंग को सक्षम कर सकते हैं।

भारत संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक गठबंधन (जीएसीइआरइ) का भी सदस्य है जो वैश्विक, उचित चक्रीय अर्थव्यवस्था परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों के अधिक टिकाऊ प्रबंधन की पक्षधर सरकारों का साथ मिलकर प्रयास करने वाला एक गठबंधन है। जीएसीइआरई संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूएनआईडीओ) द्वारा समर्थित है और इसे फरवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (यूएनईए) 5.1 के पहले खंड के साथ-साथ लॉन्च किया गया था।

भारत ने 27 जुलाई 2023 को चेन्नई में चौथी जी20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह (ईसीएसडबल्यूजी) और पर्यावरण और जलवायु मंत्रियों की बैठक के दौरान संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था उद्योग गठबंधन का शुभारंभ किया। यह गठबंधन व्यवसायों के सहयोग को बढ़ाने, अनुभव साझा करने की सुविधा प्रदान करने और विभिन्न क्षेत्रों और मूल्य शृंखलाओं में क्षमता निर्माण और चक्रीय अर्थव्यवस्था परिवर्तन प्रयासों को बढ़ाने की संभावनाएं तलाशता है।

अक्टूबर 2022 में भारत द्वारा शुरू किया गया मिशन लाइफ' (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) तीन सिद्धांतों पर आधारित एक वैश्विक आंदोलन है: जिम्मेदार उपभोग (मांग) के प्रति व्यवहार को बढ़ावा देना, बाजारों को बदलती जरूरतों (आपूर्ति) के लिए तत्परतापूर्वक कदम उठाने में सक्षम बनाना और इन पहलों (नीतियों) का समर्थन करने के लिए सरकार और औद्योगिक नीति को प्रेरित करना। भारत सरकार अपनी नीतियों में हर स्तर पर स्थायी जीवन शैली के महत्व को शामिल कर रही है और भारत का अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान जलवायु परिवर्तन से निपटने की कुंजी के रूप में स्थायी जीवन शैली पर जोर देता है।

स्थायी पर्यटन कम-कार्बन और चक्रीय व्यापार समाधानों में परिवर्तन की गति को तेज करने, ऊर्जा उत्पादन में नए अवसर पैदा करने, परिवहन उत्सर्जन को कम करने और पर्यटन गतिविधियों और संचालन में प्रकृति-आधारित समाधानों को एकीकृत करने में

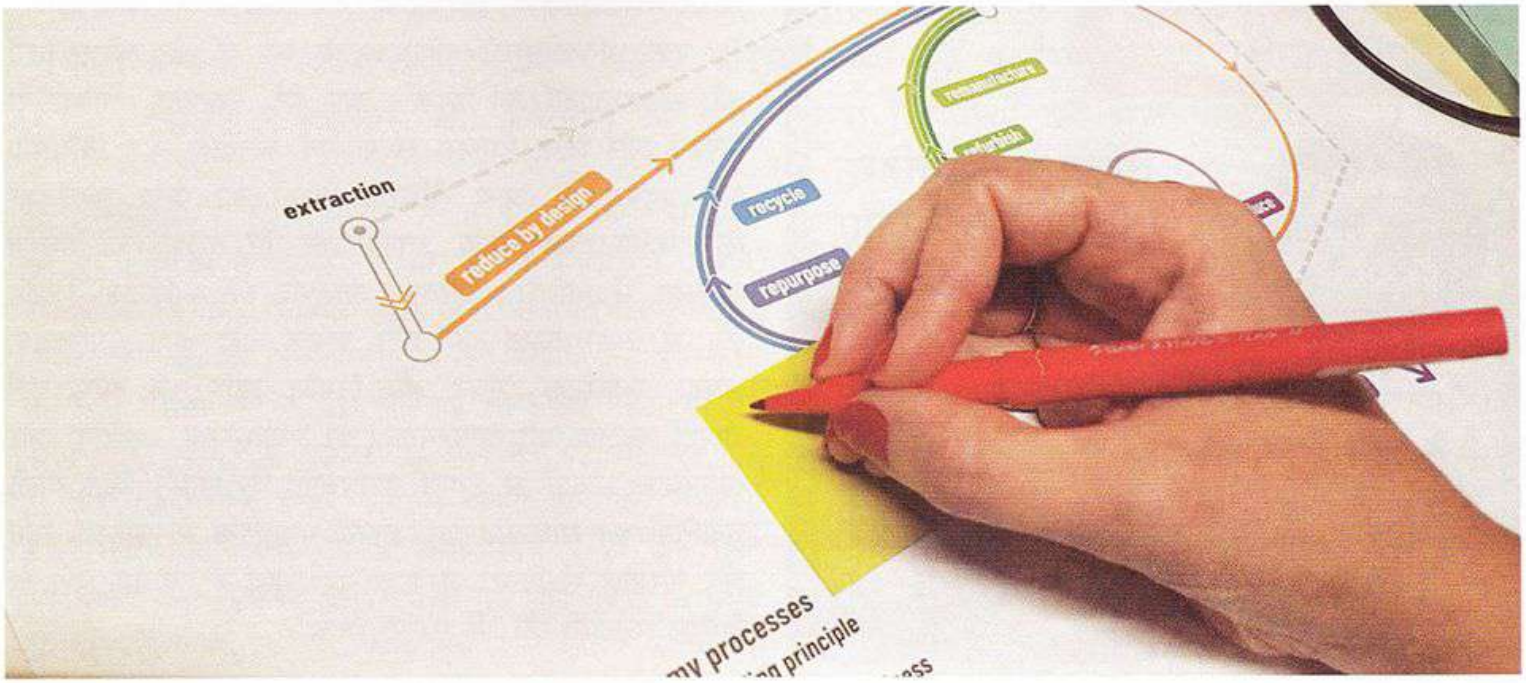

भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। 'ट्रैवल फॉर लाइफ' मिशन लाइफ के साथ जुड़ा एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य पर्यटकों और पर्यटन व्यवसायों के बीच बड़े स्तर पर व्यवहार परिवर्तन लाना है जिससे पर्यावरण संरक्षण और जलवायु संबंधी कार्रवाई पर अहम प्रभाव पड़ेगा। नई दिल्ली के नेताओं का घोषणापत्र जिम्मेदार और टिकाऊ स्मार्ट गंतव्य स्थलों के विकास में 'ट्रैवल फॉर लाइफ' की भूमिका का संज्ञान लेता है। जून 2023 में गोवा में आयोजित जी20 की चौथी पर्यटन कार्य समूह की बैठक के दौरान भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने यूएनईपी और संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्ल्यूटीओ) के सहयोग से एक विषयगत कार्यक्रम आयोजित किया जिसका शीर्षक था- 'पर्यटन में प्लास्टिक की एक चक्रीय अर्थव्यवस्था की ओर - वैश्विक पर्यटन प्लास्टिक पहल।' इस कार्यक्रम में पंजाब राज्य (भारत), सतत पर्यटन के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सोसाइटी ऑफ इंडिया वैश्विक पर्यटन प्लास्टिक पहल (जीटीपीआई) में शामिल हुए। जीटीपीआई का लक्ष्य प्लास्टिक की चक्रीय अर्थव्यवस्था के लिए एक साझी परिकल्पना के अनुरूप पर्यटन क्षेत्र को एकजुट करना और प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए ठोस समाधान विकसित करने के लिए पर्यटन व्यवसायों और गंतव्य स्थलों के साथ सहयोग करना है।

यह स्वागत योग्य है कि भारत सरकार द्वारा ऐसे उत्साहवर्धक कदम उठाए जा रहे हैं जो चक्रीय और हरित आर्थिक विकास में परिवर्तन को आगे बढ़ाएंगे और संबंधित सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होंगे।

यूएनईपी की चक्रीय अर्थव्यवस्था परिवर्तन को सशक्त बनाने के लिए कार्रवाई का समर्थन करने की प्रतिबद्धता

एसडीजी 12 के तहत 12 संकेतकों में से 8 के कर्ता-धर्ता के रूप में कार्य करने वाली यूएनईपी का लक्ष्य सतत उपभोग और उत्पादन (एससीपी) व्यवस्था में बदलाव को बढ़ावा देना और सक्षम करना है।

जीवन चक्र पहल, सतत विकास लक्ष्यों के लिए वैश्विक अवसर (जीओ4एसडीजी), अंतरराष्ट्रीय संसाधन पैनल (आईआरपी), सतत उपभोग और उत्पादन पर कार्यक्रमों की 10-वर्षीय रूपरेखा, और सतत उपभोग और उत्पादन के लिए हॉटस्पॉट विश्लेषण (एससीपी-एचएटी) यूएनईपी द्वारा पेश किए गए कुछ साधन, प्लेटफॉर्म और संरचनाएं हैं जो सर्कुलरिटी और टिकाऊ उपभोग और उत्पादन के लिए वैश्विक कार्रवाई में तेजी लाने में सहायता करते हैं।

यूएनईपी सहभागी संगठनों के सहयोग से जीवनशैली पर नवीनतम विज्ञान-आधारित साक्ष्य प्रदान करने के लिए काम करता है। 2021 में प्रकाशित '1.5 डिग्री जीवनशैली: सभी के लिए उचित उपभोग स्थान की ओर' पर यूएनईपी की रिपोर्ट ने जी20 देशों में से दस में जीवनशैली संबंधित कार्बन फुटप्रिंट की जांच की और कैसे उन फुटप्रिंट को कम किया जाए उस पर नीतिगत सुझाव पेश किये।

भारत में यूएनईपी राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को विभिन्न क्षेत्रों (ऊर्जा, कपड़ा, फैशन, प्लास्टिक, पर्यटन आदि) में सर्कुलरिटी और संसाधन दक्षता को मुख्यधारा में लाने और विश्लेषणात्मक अध्ययन करने और सक्षम बनाने के लिए सर्वोत्तम तौर-तरीकों को साझा करने में तकनीकी सहायता प्रदान करता है। सतत सार्वजनिक खरीद और इको-लेबलिंग जैसे नीतिगत साधनों के माध्यम से हरित आर्थिक विकास की ओर परिवर्तन को सक्षम बनाता है।

अत्याधुनिक विज्ञान, समन्वय और समर्थन के माध्यम से यूएनईपी भावी पीढ़ियों के हितों से समझौता किए बिना राष्ट्रों और लोगों को अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रेरित करने, अवगत कराने और सक्षम बनाने को कायम रखेगा। ❑